भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4108

19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गोवा के लिए स्वीकृत और संवितरित निधि

†4108. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गोवा के लिए स्वीकृत और संवितरित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई निधि संवितरण हेतु लंबित है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गोवा राज्य सरकार अथवा संबंधित कंपनी द्वारा प्रस्तुत निधि उपयोग प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा एससीएम के अंतर्गत उक्त कार्यों को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कार्यों में विलंब के लिए संबंधित पक्षों पर कितना जुर्माना, यदि कोई हो, लगाया गया है; और

(ङ) गोवा राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में प्रस्तुत की गई स्मार्ट सिटी परियोजना संबंधी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के तहत, केंद्र सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए कुल 48,000 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा है। 30.11.2024 तक, एससीएम के तहत कुल 500 करोड़ रुपये में से 441 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता गोवा राज्य को जारी की गई है, जिसमें से 411 करोड़ रुपये (जारी केंद्रीय सहायता का 93%) का उपयोग किया जा चुका है। की गई मांगों, राज्य के मैचिंग हिस्से को जारी किए जाने और अब तक शहरों को जारी केंद्रीय और राज्य सहायता के उपयोग के आधार पर स्मार्ट सिटीज को निधियां जारी की जाती हैं।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त अनुरोध पर, एससीएम की अवधि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी गई है। एससीएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, शहरी स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा किया जाएगा। एसपीवी स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना, मूल्यांकन, अनुमोदन, निधि जारी, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन करेगा। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित एसपीवी की है क्योंकि एससीएम के तहत सभी परियोजना अनुबंध एसपीवी और संबंधित पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से निष्पादित किए जाते हैं। स्मार्ट सिटीज लगातार परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति और जियोटैग की गई संपत्तियों की वास्तविक प्रगति को भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर अपडेट कर रहे हैं और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

*****